STUDY CIRCLE SINCE: 1994

प्रश्न - 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) क्या है ? भारत की अर्थव्यवस्था में PSU की क्या भूमिका है ? भारत में PSU को पुनर्जीवित करने के लिये भारतीय सरकार के प्रयासों का विश्लेषण करें । (300 शब्दों में)

उत्तर - 7 सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम :- वे उपक्रम जो सार्वजनिक कल्याण (Public Welfare) के लिये स्थापित किये गये है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) कहलाते है। इन उपक्रमों या संगठनों की स्वामी सरकार होती है। तथा सरकार ही इनका प्रबन्ध करती है। सार्वजनिक उपक्रमों में न्यूनतम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार की होती है।

भारत में इनका आरंभ मौर्यकाल से हो गया था तथा अकबर के काल और ब्रिटिश काल में इसका विकास हुआ । निगम हो अथवा सरकारी कम्पनी, ये PSU के स्वरूप माने जाते है।

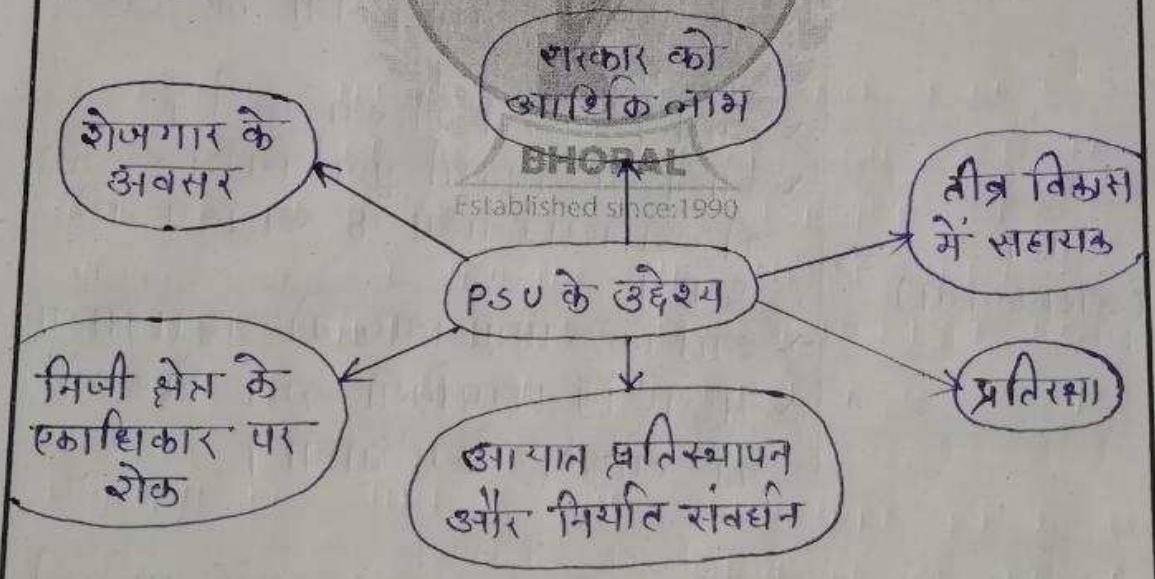

BHOPAL
Established since:1990

=> सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

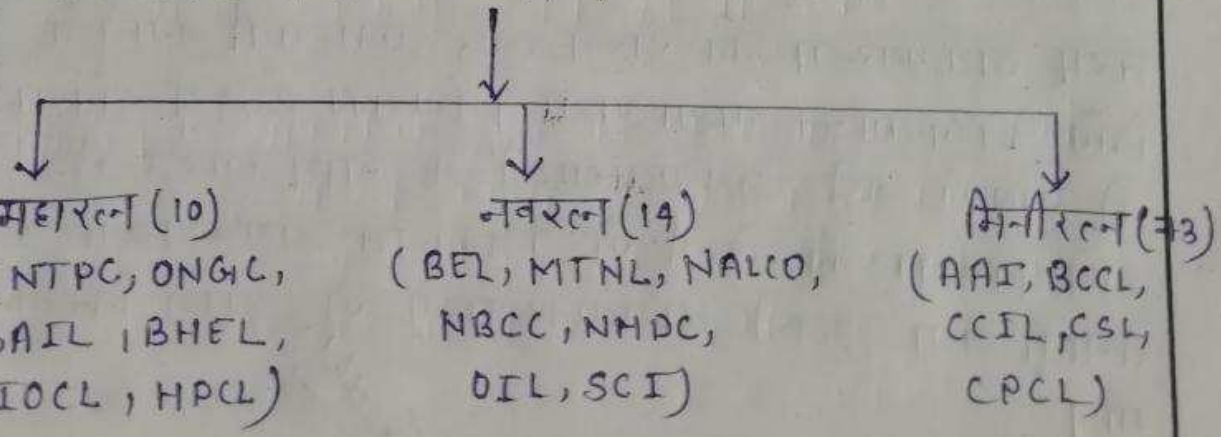

⇒ भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका

1) पूंजी निर्माण में योगदान :- प्रथम पंचवर्षीय योजना में 54 % पूंजी तथा नवीं पंचवर्षीय योजना में 33 % पूंजी निवेशित की गई। अतः इन क्षेत्रों ने पूंजी निर्माण में सहायता की।

2) आर्थिक अधोसंरचना (Economic infrastructure)

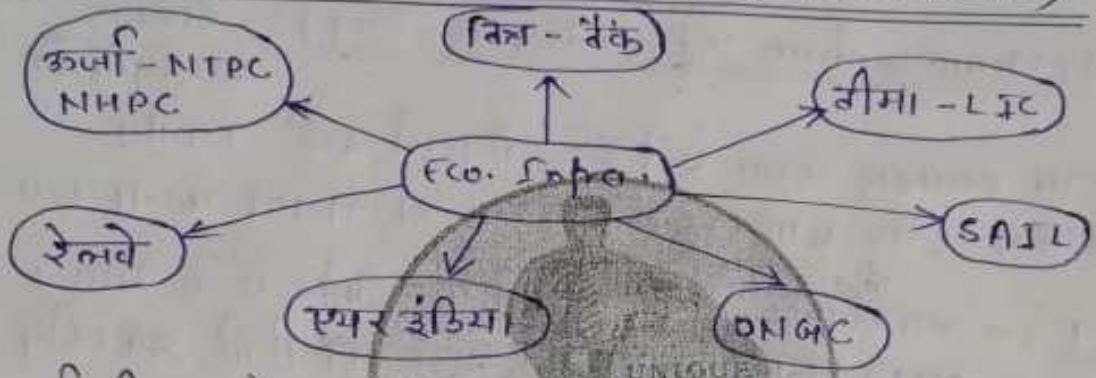

सार्वजनिक क्षेत्र उपरोक्त आर्थिक अधोसंरचना प्रदान करते है।

3) लोकनिगम और सरकारी कम्पनियां लोककल्याण और सरकार के लिये फायदेमंद काम कर रही है।

BHOPAL
Established since:1990

4) लोकनिगम और कंपनियां देश में २० लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहें ज है जो संगठित क्षेत्र के रोजगार का ५ % है।

5) यह राष्ट्रीय आय में भी अपना योगदान देते है। भारत की राष्ट्रीय आय का २०% हिस्सा इन्हीं पर निर्भर करता है।

6) सार्वजनिक क्षेत्र आयात, निर्यात प्रतिस्थापना का कार्य भी करते है।

⇒ भारतीय सरकार द्वारा PSU को पुनर्जीवित करने हेतु उठाये गये कदम

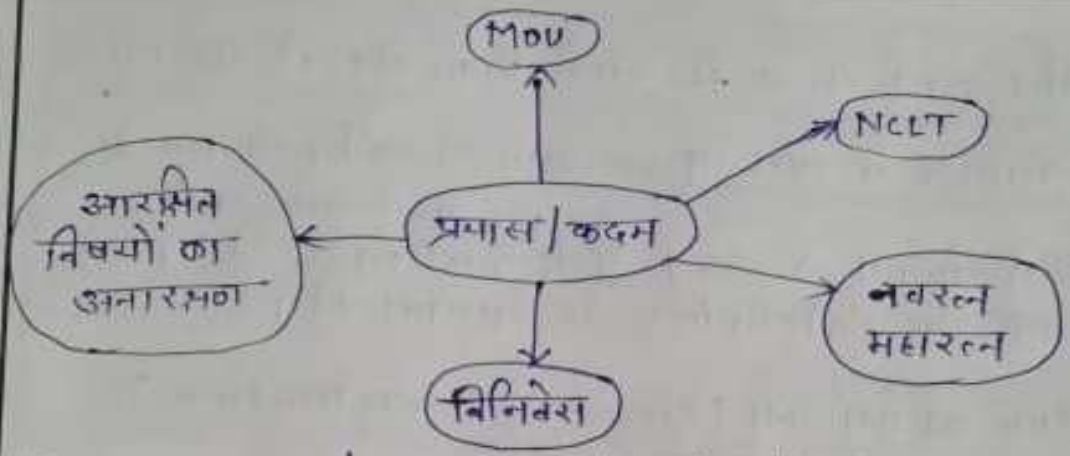

(1) MOU (Memorandum of Understanding) :- सरकार कम्पनियों से MOU पर हस्ताक्षर करता रही है, जिससे इन्हें वित्तीय अनुशासन और आर्थिक स्वायत्तता का वायदा करना पड़ता है।

(2) NCLT :- सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमार इकाईयों के मामले NCLT निपटाता है। जो इन्हें तकनीकी, प्रबंधकीय वित्तीय मदद आदि मुहैया करा सकता है।

(3) अनारक्षण :- सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिये आरक्षित विषयों का अनारक्षण किया गया है। अब पब्लिक सेक्टर में केवल तीन क्षेत्र - आण्विक ऊर्जा, रेल यातायात तथा आण्विक खनिज ही आरक्षित रह गये हैं। जैसे - BSNL, राष्ट्रीयकृत बैंक, दूरदर्शन आदि की गुणवत्ता अनारक्षण से बेहतर हुई है।

(4) कम्पनियों को उपाधि या दर्जा :- सार्वजनिक क्षेत्र के श्रेष्ठ निष्पादकों को नवरत्न, महारत्न तथा मिनीरत्न का दर्जा दिया गया है तथा इन्हें अधिक स्वायत्ता प्रदान की गई है।

(5) विनिवेश :- सार्वजनिक क्षेत्रों की संपत्तियों और इनकी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचना विनिवेश कहलाता है। ऐसा करने से इसमें निजी प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सकता है। यह दो प्रकार का होता है -
(i) सामरिक विनिवेश (ii) गैर सामरिक विनिवेश

निष्कर्ष :- सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थापना जन कल्याण, देश का आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संतुलन, आयात विकल्प आदि उद्देश्यों पर निर्भर है, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

Excellent!